निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र विचार व अपराध निरोधक मुख्य हिन्दी राष्ट्रीय समाचार पत्र

दिल्ली क्राईम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा

DELHI CRIME WA BHRASHTACHAR VIRODHI MORCHA

www.delhicrimepress.com
info@delhicrimepress.com

RNI No. DELHIN/2005/15378 ● DCP Lic. No. F-2(D-9)PRESS/2005 ● वर्ष-22 ● 01 जून 2026 से 30 जून 2026 ● अंक-11 एवं 12 ● पृष्ठ-8 ● मूल्य-10रू

10 वर्षों से बढ़ रही विशाल थायरॉइड गांठ का महाराजा अग्रसेन अस्पताल में सफल जटिल ऑपरेशन

वरिष्ठ एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जन डॉ. विवेक अग्रवाल

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में वरिष्ठ एवं अनुभवी एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जन डॉ. विवेक अग्रवाल एवं उनकी विशेषज्ञ टीम ने एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 60 वर्षीय महिला की विशाल थायरॉइड गांठ (मल्टीनोड्यूलर गॉयटर) को सफलतापूर्वक निकाला। मरीज पिछले लगभग 10 वर्षों से गर्दन में बढ़ती सूजन से परेशान थीं, जो पिछले 6 महीनों में तेजी से बढ़ने लगी थी। डॉ. विवेक अग्रवाल एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जरी के क्षेत्र में लंबे अनुभव वाले विशेषज्ञ सर्जन हैं और जटिल थायरॉइड, पैराथायरॉइड एवं ब्रेस्ट सर्जरी में विशेष दक्षता रखते हैं। उन्होंने अब तक अनेक जटिल एंडोक्राइन सर्जरी सफलतापूर्वक की हैं।

मरीज की समस्या और ऑपरेशन की आवश्यकता: मरीज की गर्दन में मौजूद थायरॉइड की गांठ अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वह बाहर से स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। मरीज को गर्दन में भारीपन और असहजता महसूस होने लगी थी। चिकित्सकों के अनुसार यदि इस स्थिति का समय पर इलाज न किया जाता, तो भविष्य में सांस लेने, निगलने तथा बोलने में गंभीर दिक्कतें उत्पन्न हो सकती थीं। जांच एवं अल्ट्रासाउंड में पाया गया कि मरीज के दोनों थायरॉइड लोब अत्यधिक बढ़े हुए थे तथा उनमें कई बड़े सॉलिड और सिस्टिक नोड्यूल्स मौजूद थे। कुछ गांठों का आकार लगभग 3 सेंटीमीटर तक पहुंच चुका था। तेजी से बढ़ती गांठ को देखते हुए विशेषज्ञ टीम ने तत्काल सर्जरी का निर्णय लिया।

क्या होती है टोटल थायरॉयडेक्टॉमी? - टोटल थायरॉयडेक्टॉमी (Total Thyroidectomy) एक अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल सर्जरी है, जिसमें पूरी थायरॉइड ग्रंथि को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह सर्जरी विशेष रूप से तब आवश्यक होती है जबः थायरॉइड की गांठ बहुत बड़ी हो जाए ,गांठ तेजी से बढ़ रही हो,सांस या भोजन नली पर दबाव पड़ रहा हो,कैंसर की आशंका हो,मरीज को निगलने या बोलने में परेशानी हो रही हो,डॉ. विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में ऑपरेशन के दौरान पूरी थायरॉइड ग्रंथि को सावधानीपूर्वक निकाला गया। लंबे समय से बढ़ रही विशाल गांठ के कारण आसपास की नसें, रक्त वाहिनियां एवं महत्वपूर्ण संरचनाएं अपनी सामान्य स्थिति से हट चुकी थीं, जिससे सर्जरी तकनीकी रूप से और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई थी। ऑपरेशन के दौरान किन बातों का रखा गया विशेष ध्यान? सर्जरी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व (Recurrent Laryngeal Nerve) को सुरक्षित रखना। यह नस हमारी आवाज को नियंत्रित करती है। यदि ऑपरेशन के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो जाए, तो मरीज की आवाज बैठ सकती है या स्थायी बदलाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करने वाली छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पैराथायरॉइड ग्रंथियों को भी सुरक्षित रखना जरूरी था। ऑपरेशन के दौरान एक पैराथायरॉइड ग्रंथि की रक्त आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए टीम द्वारा पैराथायरॉइड ऑटोट्रांसप्लांटेशन (Parathyroid Autotransplantation) किया गया। इस उन्नत प्रक्रिया में पैराथायरॉइड ऊतक को शरीर के दूसरे सुरक्षित हिस्से में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि उसकी कार्यक्षमता बनी रहे और मरीज में भविष्य में कैल्शियम की गंभीर कमी न हो। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया केवल अनुभवी एंडोक्राइन सर्जनों द्वारा ही की जाती है। समय पर ऑपरेशन न कराने के क्या खतरे हो सकते हैं? विशेषज्ञों के अनुसार थायरॉइड की बड़ी गांठ को लंबे समय तक नजरअंदाज करना गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इनमें शामिल हैं: ,श्वासनली पर दबाव पड़ने से सांस लेने में कठिनाई,भोजन नली दबने से निगलने में परेशानी, आवाज में बदलाव या भारीपन, गर्दन में दर्द एवं लगातार असहजता, अचानक गांठ का तेजी से बढ़ना, कुछ मामलों में कैंसर विकसित होने की संभावना, डॉक्टरों का कहना है कि गर्दन में किसी भी प्रकार की सूजन, तेजी से बढ़ती गांठ, आवाज में बदलाव या निगलने में परेशानी होने पर तुरंत विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए। डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया, थायरॉइड की गांठ को सामान्य सूजन समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और सही उपचार से मरीज को भविष्य की गंभीर जटिलताओं से बचाया जा सकता है। इस मरीज में गांठ का आकार काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन हमारी टीम ने सावधानीपूर्वक सफल सर्जरी करते हुए महत्वपूर्ण नसों और पैराथायरॉइड ग्रंथियों को सुरक्षित रखा। जटिल थायरॉइड सर्जरी में अनुभवी सर्जिकल टीम और समय पर निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सर्जरी में शामिल टीम इस जटिल सर्जरी में कई विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर्जिकल टीम में: डॉ. विवेक अग्रवाल - वरिष्ठ एंडोक्राइन एवं ब्रेस्ट सर्जन, डॉ. सुदीप्त भट्टाचार्य, डॉ. नसरीन, एनेस्थीसिया टीम में,डॉ. सुधीर (एनेस्थीसियोलॉजिस्ट) ऑपरेशन थिएटर एवं मरीज की देखभाल में :आशा सिस्टर, दिव्या सिस्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

दिल्ली क्राइम प्रेस का धामकेदार सफर सफलता पूर्वक जारी है यह दूसरे सक्सेस सेमिनार के फोटो मे साफ दिख रहा है अब तो ऐसे सेमिनार की देश के अलग अलग हिस्से मे जबरदस्त और शानदार झडी लगने वाली है

dc pess JUNE 2026:Layout 1 09-06-2026 18:04 Page 2

अब ब्लड प्रेशर नापने के लिए पट्टे की जरूरत नहीं; कलाई पर पहनने वाला यह छोटा सा सेंसर रखेगा आपकी हर धड़कन पर नजर!

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वायरलेस और हल्का डिवाइस तैयार किया है, जो बिना बाजू पर भारी पट्टा बांधे, चलते-फिरते बिल्कुल सटीक ब्लड प्रेशर माप सकता है।

नई दिल्ली / शिकागो
विशेष संवाददाता द्वारा: अगर आपको अक्सर अपना ब्लड प्रेशर यानी बीपी नापना पड़ता है, तो आप उस असहज करने वाले पल से अच्छी तरह वाकिफ होंगे जब डॉक्टर आपकी बाजू पर एक बड़ा सा पट्टा लपेटते हैं और उसमें हवा भरते हैं। वह दबाव कभी-कभी दर्दनाक भी हो जाता है। लेकिन आने वाले समय में आपको इस परेशानी से हमेशा के लिए आजादी मिल सकती है। शिकागो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस (UIC) के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जो पारंपरिक ब्लड प्रेशर कफ को हमेशा के लिए गुजरे जमाने की बात बना सकती है। वैज्ञानिकों ने एक बेहद छोटा, पहनने योग्य वायरलेस सेंसर बनाया है, जो कलाई पर बंधी घड़ी या बैंड की तरह काम करता है और बिना किसी दबाव या दर्द के चौबीसों घंटे ब्लड प्रेशर की सटीक मॉनिटरिंग कर सकता है।

कैसे काम करती है यह नई तकनीक?

पारंपरिक बीपी मशीनें धमनियों में खून के प्रवाह को कुछ सेकंड के लिए रोककर दबाव को मापती हैं। इसके विपरीत, यूआईसी का यह नया डिवाइस 'फोटोप्लेथिस्मोग्राफी' और उन्नत एल्गोरिदम के सिद्धांत पर काम करता है। यह सेंसर त्वचा के नीचे बहने वाले खून की तरंगों और उसकी गति का विश्लेषण करता है। डिवाइस में लगे ऑप्टिकल सेंसर त्वचा पर एक विशेष लाइट छोड़ते हैं, जिससे यह पता चलता है कि दिल के धड़कने पर धमनियों में खून का फैलाव किस गति से हो रहा है। इसके बाद, इसके अंदर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर मॉडल इस डेटा को तुरंत सटीक सिस्टोलिक (यानी ऊपरी) और डायस्टोलिक (यानी नीचे वाले) ब्लड प्रेशर नंबरों में बदल देता है।

चलते-फिरते मॉनिटरिंग: 'व्हाइट कोट सिंड्रोम' से मिलेगी राहत – इस आविष्कार की सबसे बड़ी खासियत इसका 'ऑन-द-गो' यानी चलते-फिरते काम करना है। आम तौर पर जब मरीज अस्पताल जाते हैं, तो डॉक्टरों को देखकर घबराहट के कारण उनका बीपी अचानक बढ़ जाता है, जिसे चिकित्सा विज्ञान में 'व्हाइट कोट हाइपरटेंशन' कहा जाता है। इसके कारण कई बार

डॉक्टरों को मरीज का सही ब्लड प्रेशर पता नहीं चल पाता। यह नया सेंसर मरीज के सामान्य दैनिक जीवन–जैसे सोते, जागते, टहलते या काम करते समय– लगातार बीपी रिकॉर्ड करता रहता है। इससे डॉक्टरों को मरीज की सेहत का एक वास्तविक और मुकम्मल डेटा मिल सकेगा।

इस डिवाइस के प्रमुख फायदे:

दर्द और दबाव से मुक्ति: बाजू पर पट्टा बांधकर नसों को भींचने वाले दर्दनाक दबाव से पूरी तरह छुटकारा।

लगातार ट्रैकिंग: यह हर कुछ घंटों में बीपी नापने के बजाय लगातार निगरानी रखता है, जिससे दिल के दौरे या स्ट्रोक के खतरों को समय रहते पकड़ा जा सकता है।

बेहद हल्का और वायरलेस: इसे कलाई पर किसी स्मार्टवॉच की तरह आसानी से चौबीसों घंटे पहना जा सकता है।

त्वचा के रंग से अप्रभावित: शोधकर्ताओं के अनुसार, इस सेंसर को इस तरह ट्यून किया गया है कि यह अलग-अलग स्किन टोन वाले लोगों पर भी बिल्कुल सटीक परिणाम देता है।

साइलेंट किलर पर लगेगी लगाम

हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को दुनिया भर में 'साइलेंट किलर' माना जाता है, क्योंकि इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन यह धीरे-धीरे दिल और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि यूआईसी का यह नया कफलेस डिवाइस चिकित्सा जगत में गेम-चेंजर साबित होगा। हालांकि यह तकनीक अभी व्यावसायिक रूप से बाजार में आने के अंतिम चरणों और विनियामक मंजूरी की प्रक्रियाओं से गुजर रही है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब बीपी नापने का पारंपरिक कफ केवल मेडिकल कॉलेजों के म्यूजियम में ही देखने को मिलेगा।

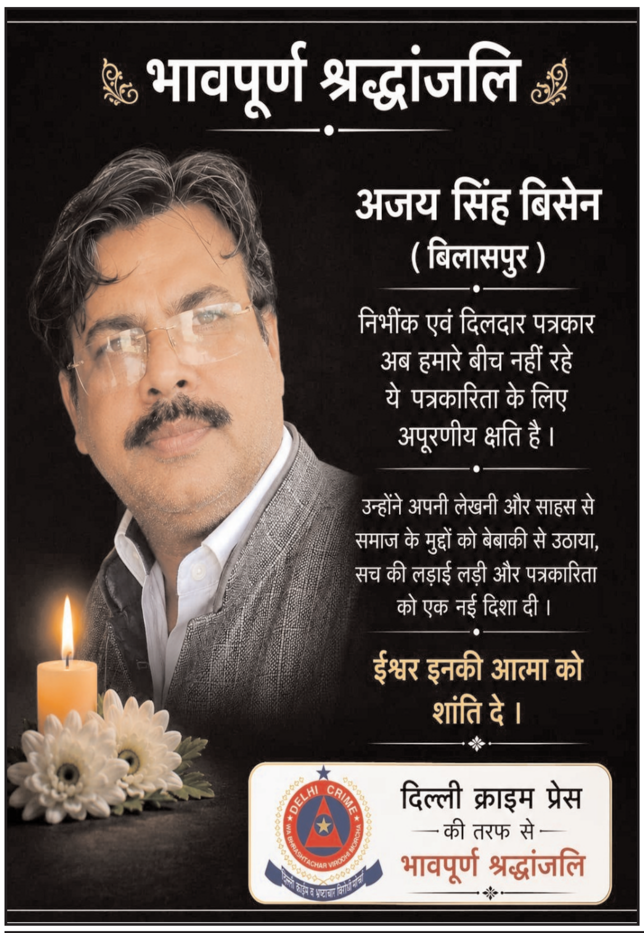

कुलजीत सिंह चहल ने खान मार्केट में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने सोमवार को खान मार्केट में चल रहे विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया और स्थल पर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया कि खान मार्केट में एनडीएमसी द्वारा मध्य लेन के सुधार के लिए एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम, उन्नत फुटपाथ एवं फर्श बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.21 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंटरलॉकिंग पेवर्स खराब हो चुके थे, जिनकी बार-बार मरम्मत करनी पड़ती थी

और यह लेन भारी पैदल यातायात एवं व्यावसायिक गतिविधियों से प्रभावित रहती है, जिससे आधुनिक और टिकाऊ अवसंरचना की आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि इस पुनर्विकास परियोजना में नई ड्रेनेज नेटवर्क, सीवर कनेक्शन चेंबर, जल आपूर्ति अवसंरचना, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डक्ट, ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग, इंटरलॉकिंग पेवर्स और स्टेनलेस स्टील डस्टबिन की स्थापना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का उद्देश्य देश की राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र में नागरिक सेवाओं, सौंदर्य और पैदल यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाना है। कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि अब तक ड्रेनेज लाइन बिछाने, सिल्ट कलेक्शन चेंबर निर्माण, जल आपूर्ति पाइपलाइन एवं वाल्व लगाने, सीवर निरीक्षण चेंबर, इलेक्ट्रिकल फीडर पिलर चेंबर और अन्य यूटिलिटी कनेक्शन चेंबर जैसे कई कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है ताकि दुकानदारों, आगंतुकों और निवासियों को न्यूनतम असुविधा हो। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती संकरी छह मीटर चौड़ी लेन के नीचे बड़ी संख्या में भूमिगत बिजली केबल और अन्य यूटिलिटी सेवाएं हैं।

दिल्ली सरकार, सीएसआईआर-सीआरआरआई और एसपीए के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसी के तहत सोमवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीआरआरआई) और स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल के अंतर्गत दिल्ली की शहरी सड़कों के सौंदर्यीकरण, वैज्ञानिक पुनर्रचना और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए ह्यस्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पेविंग ऐंड ग्रीनिंग ऑफ अर्बन रोडह्व लागू किया जाएगा। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सहित सीएसआईआर-सीआरआरआई के वैज्ञानिक, एसपीए के विशेषज्ञ और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह एमओयू राजधानी में सड़क निर्माण, रखरखाव, रोड सेफ्टी, ग्रीनिंग, स्ट्रीटस्केप डेवलपमेंट एवं धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक मानकीकृत, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन फ्रेमवर्क विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल नई सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा अर्बन रोड इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं,

जो पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण, ट्रैफिक लोड, वायु प्रदूषण और जलभराव जैसी चुनौतियों को देखते हुए अब सड़कों की योजना और रखरखाव को पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं डेटा आधारित प्रणाली से संचालित करना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एमओए के तहत दिल्ली में पहली बार व्यापक रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएएमएस) विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से राजधानी की सड़कों की वर्तमान स्थिति, उन पर पड़ने वाले यातायात के दबाव, उनकी संरचनात्मक क्षमता, मरम्मत की आवश्यकता और उनकी उपयोग अवधि का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के अंतर्गत सड़कों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, उनकी स्थिति का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और रखरखाव की योजना बनाई जाएगी। इससे सार्वजनिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग हो सकेगा और सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन में सुधार आएगा। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य दिल्ली को धूल-मुक्त सड़कों के मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाना भी है।

इसके तहत सड़कों के किनारे वैज्ञानिक तरीके से हरित पट्टियां विकसित की जाएंगी, स्थानीय प्रजातियों के पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा तथा सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग के माध्यम से सड़कों को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सड़कों के स्लोप और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को पुनर्गठित किया जाएगा। पेवमेंट डिजाइन में ऐसी तकनीक का उपयोग होगा जो भूजल रिचार्ज में सहायक हो ताकि मॉनसून में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। एमओए के तहत सीएसआईआर-सीआरआरआई सड़क इंजीनियरिंग, पेवमेंट टेक्नोलॉजी, रोड सेफ्टी और एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा, जबकि एसपीए शहरी डिजाइन, स्ट्रीटस्केप प्लानिंग, पब्लिक स्पेस डेवलपमेंट, अर्बन लैंडस्केपिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देगा।

सम्पादकीय, नरेंद्र कुमार

न्यायालय के आलोक में बेटी का अधिकार

भारतीय न्यायपालिका ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि न्याय हमेशा समाज की बदलती वास्तविकताओं को स्वीकार करते हुए समानता, गरिमा और मानवीय अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया हालिया निर्णय, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति एवं आश्रित कोटे के लाभों से बाहर रखने को असंवैधानिक ठहराया गया है, भारतीय न्यायिक इतिहास में महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय कहलाएगा । वास्तव में यह निर्णय उस सोच को भी चुनौती देता है जो विवाह के बाद बेटी को उसके माता-पिता के परिवार से अलग मान लेने की प्रवृत्ति रखती है। कई बार माता-पिता के लिए भी और कई बार परिवार के भाई एवं अन्य कुटुम्बजनों के लिए। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने स्पष्ट कहा कि विवाहित पुत्री को ह्यपरिवारह्न की परिभाषा से बाहर रखना मनमाना, अनुचित तथा संविधान के समानता सिद्धांत के विपरीत है। आज न्यायालय की इस संबंध में अत्यंत सारगर्भित टिप्पणी बता रही है कि विवाह न तो बेटी और उसके माता-पिता के बीच के संबंध को समाप्त करता है और न ही यह मान लेने का कोई आधार देता है कि वह अब अपने परिवार पर आश्रित नहीं रही। इसके साथ ही यह कथन भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त भी करता है, जहां आज असंख्य विवाहित बेटियां अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक संबल का आधार बनती हैं तथा कठिन परिस्थितियों में परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि कुलसुम निशा के मामले में न्यायालय ने कानून की व्याख्या नवीन अर्थों के साथ की है, जिसमें जीवन की वास्तविकताओं को महत्व दिया गया। याचिकाकर्ता अपनी माता के निधन के पश्चात अपनी बहनों, जिनमें एक दृष्टिबाधित बहन भी शामिल है, के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभा रही है। वे अपनी माता के साथ रहती थीं और उचित मूल्य की दुकान के संचालन में सहयोग करती थीं। इसके बावजूद, इसलिए उनकी अर्जी अस्वीकार कर दी गई थी क्योंकि वे विवाहित थीं। अब न्यायालय ने इस आधार को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह निर्णय बताता है कि न्यायपालिका व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों को प्राथमिकता देती है, न कि रूढ़िगत धारणाओं को। वास्तव में निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना का विस्तार है। संविधान के अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यदि विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जा सकता है तो विवाह के कारण विवाहित पुत्री को उस अधिकार से वंचित करना स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव ही है। उच्चतम न्यायालय ने इसी असमानता को समाप्त करते हुए एक बार फिर यह संदेश दिया है कि अधिकार व्यक्ति की योग्यता, आवश्यकता और वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्धारित होंगे, न कि उसके लिंग या वैवाहिक स्थिति के आधार पर।

दिल्ली क्राइम प्रेस की खबर का असर, 3 दिन से लापता पिल्ले सकुशल बरामद

सबलपुर बितरा पिछले तीन दिनों से लापता दो पालतू पिल्ले आखिरकार सकुशल बरामद कर लिए गए। पिल्लों के मालिक लव कुमार ने उनकी गुमशुदगी की सूचना सोशल मीडिया और स्थानीय ग्रुपों में साझा की थी, जिसके बाद मामला तेजी से लोगों तक पहुंचा। दिल्ली क्राइम प्रेस द्वारा पिल्लों के लापता होने की खबर प्रकाशित किए जाने के बाद ग्रामीणों का भी ध्यान इस ओर गया। खबर प्रसारित होने के कुछ समय बाद गांव के कई लोगों ने फोन कर सूचना दी कि दोनों पिल्ले गांव के बाहर देखे गए हैं। सूचना मिलते ही मालिक मौके पर पहुंचे और दोनों पिल्लों को सुरक्षित अपने साथ घर ले आए। पिल्लों के मिलने से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है।लव कुमार ने पिल्लों की तलाश में सहयोग करने वाले सभी ग्रामीणों तथा दिल्ली क्राइम प्रेस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाचार के माध्यम से सूचना अधिक लोगों तक पहुंची, जिससे पिल्लों को ढूंढने में मदद मिली। ग्रामीणों ने भी राहत जताते हुए कहा कि तीन दिन से चल रही "पिल्ला खोज अभियान" का आखिरकार सुखद अंत हो गया। **रिपोर्ट - लव कुमार**

विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएम उमेश मिश्रा ने लगाया अमरूद का पौधा, 'एक पेड़ माँ के नाम' लगाने की अपील

मुजफ्फरनगरः विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वयं फलदार (अमरूद) का पौधा रोपित कर समस्त जनपदवासियों को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश दिया। यह पर्यावरण पहल केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 05 जून से 21 जून 2026 तक संचालित किए जा रहे "सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान" अभियान के अंतर्गत की गई है। इस महा-अभियान का उद्देश्य समेकित जन-कल्याण और बड़े स्तर पर जन-जागरूकता फैलाना है प्रकृति संरक्षण को मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा, "हमारा लगाया हुआ एक-एक पौधा जब आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनेगा, तभी हमारा पर्यावरण समृद्ध और पूरी तरह सुरक्षित होगा।" उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक अपनी माता के सम्मान में "एक पेड़ माँ के नाम" अवश्य लगाए और केवल पौधा लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लिया संकल्पकलेक्टे्रट परिसर में आयोजित इस महा-अभियान में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी उपस्थित जनों ने मिलकर जिले को हरित व स्वच्छ बनाने और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। **(रिपोर्टरः निखिल सैनी, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)**

सबलपुर बितरा में अन्नपूर्णा भवन को लेकर विवाद, ग्राम प्रधान व लेखपाल (पटवारी) की मिलीभगत के आरोप; ग्रामीणों ने जांच की मांग की

नजीबाबाद (बिजनौर)। विकासखंड नजीबाबाद के ग्राम सबलपुर बितरा में प्रस्तावित अन्नपूर्णा भवन के निर्माण स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के अनेक लोगों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा राशन डीलर ने चयनित स्थान पर आपत्ति जताते हुए ग्राम प्रधान एवं लेखपाल (पटवारी) की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की समतल एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद अन्नपूर्णा भवन का निर्माण गड्ढों वाली जगह पर कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि जनसुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर अनुपयुक्त स्थान का चयन किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार समतल भूमि पर भवन निर्माण होने से राशन वितरण एवं अन्य कार्यों का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा, जबकि वर्तमान में चयनित स्थान पर बरसात और आवागमन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है।

इस निर्णय पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, राशन डीलर तथा कई गांववासियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। गांववासियों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि विभागीय अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर समतल भूमि एवं वर्तमान चिन्हित स्थान दोनों का निष्पक्ष निरीक्षण करे तथा तकनीकी मानकों और जनहित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान का चयन सुनिश्चित करे। ग्रामीणों का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और अन्नपूर्णा भवन के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो सकेगा।यह संस्करण अखबार में छपने वाली खबर की शैली में तैयार किया गया है और पहले वाले ड्राफ्ट से अलग दिखेगा।
(रिपोर्ट - लव कुमार)

सांसद विद्युत वरण महतो ने किया झारखंड क्षत्रिय संघ भवन के प्रथम तल का भूमिपूजन

जमशेदपुर (कदमा): झारखंड क्षत्रिय संघ, कदमा इकाई के लिए आज का दिन अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक रहा। झारखंड क्षत्रिय संघ भवन के प्रथम तल्ला (1st Floor) निर्माण कार्य का भूमिपूजन एवं आधारशिला स्थापना कार्यक्रम माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी के कर-कमलों द्वारा विधिवत संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो जी ने झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा समाजहित और जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। **(ट्रेनी रिपोर्टर: अंकित कुमार BVC592875)**

Helpline No. 7982654944
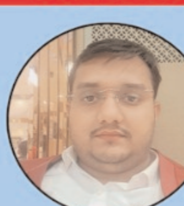
ABHISHEK KUMAR
DELHI STATE HEAD
DELHI CRIME
WA
BHRASHTACHAR VIRODHI MORCHA NATIONAL NGO
भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़
NITII AAYOG DARPAN REGN. NO. DL/2020/0260865 REGN. NO. S/RS/DW(SW)/1646/2019
C-1/511, NEW YADAV ENCLAVE, PREM NAGAR-3, NEAR CHAUDHARY BALDEV SINGH MODEL SCHOOL,DELHI-110086

dc pess JUNE 2026:Layout 1 09-06-2026 18:04 Page 4

दिल्ली क्राइम की टीम लीडर आँचल जी दिल्ली क्राइम के ऑफिस में फील्ड में अपनी टीम को सर्विस और जानकारी प्रदान कर रही है

दिल्ली क्राइम के ऑफिस में अनिल सेठी जी टीम लीडरो को बिजनेस टिप्स के साथ साथ सिस्टम की पॉवर और नए अपडेट की जानकारी प्रदान करते हुए

जिला मंडला कोतवाली थाना प्रभारी शकील खान साहब जी से मुलाकात करते हुए गोपाल प्रसाद यादव और एरिया एडवाइजर रविंद्र गिरी और एक नए सदस्य

दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित, दिल्ली क्राइम ऑफिस पहुंचे पत्रकार, संगठन के बारे में चर्चा हुई

दिल्ली क्राइम प्रेस के बढ़ते कदम

दिल्ली क्राइम की स्टार लेडी लीडर रोशनी जी ने बहुत टाइम के बाद फिर से दिल्ली क्राइम के मैदान मे कदम रख दिया है

सत्य और न्याय की आवाज बनेगा दिल्ली क्राइम प्रेस डॉ संजय कुमार को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी

पत्रकारिता और समाज सेवा का संकल्प: खतौली में दिल्ली क्राइम न्यूज पेपर से जुड़े सुएब और इनाम

दिल्ली क्राइम के सुपर स्टार लीडर संजय जी अपनी टीम मे आये नए सदस्य हिमांशु को दिल्ली क्राइम का कार्ड और किट देकर सम्मानित करते हुए

दिल्ली क्राइम प्रेस के ऑफिस में फील्ड में टीम को सर्विस के साथ जानकरी भी मुहैया कराइ जा रही है

दिल्ली क्राइम प्रेस के टीम लीडर एस के हसन ओखला जामिया नगर नई दिल्ली में टीम को सहयोग और प्रचार कर रहे है

दिल्ली क्राइम प्रेस टीम लीडर गोपाल प्रसाद यादव और रविंद्र गिरी एरिया एडवाइजर और दो अन्य नए सदस्य सुरेश माहुकर और लोकेश तिवारी एसपी राजेश रघुवंशी जी से मुलाकात करते हुए

उत्तम नगर में दिल्ली क्राइम की धूम

भारतीय जीवन बीमा से वरिष्ठ अभिकर्ता ने ली दिल्ली क्राइम प्रेस की सदस्यता

दिल्ली क्राइम के हैड ऑफिस गोविंद पूरी कालका जी मे दिनेश जी आंचल जी अनिता भोज जी सागिर जी अपनी अपनी टीम के साथ मीटिंग करके हर तरह की जानकारी और सर्विस देते हुए

दिल्ली क्राइम की ग्रेट लीडर नीलम गुप्ता अपनी टीम श्रीमति सिमी खेतपाल जी और नेहा शर्मा के साथ

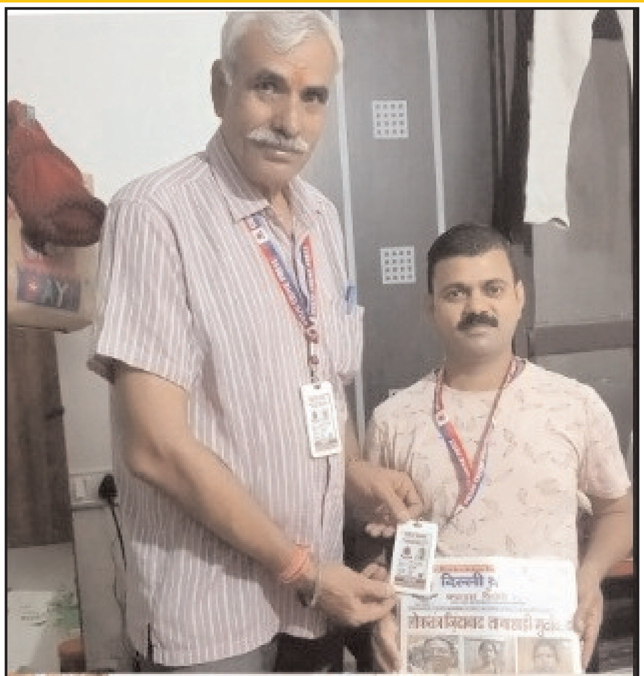

दिल्ली क्राइम प्रेस मे बिजवासन के लीडर महावीर सिंह राणा जी अपनी टीम मे आये हुए नए सदस्य उदय चौधरी जी, नारायण जी और मदन कुमार झा जी को उनके कार्ड और किट देकर सम्मानित करते हुए

गौ सेवा को समर्पित आध्यात्मिक गुरु प्रवीण देव से दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर की खास मुलाकात

दिल्ली क्राइम के गुरुग्राम ब्रांच ऑफिस मे अंबुज कश्यप जी को किया सम्मानित

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई में पश्चिम बंगाल शामिल, देशभर में योजना का विस्तार पूरा

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अब पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण विस्तार हो गया है। यह अब सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के जुड़ने से राज्य की लगभग 1.43 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपयेतक का सालाना स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। सोमवार को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की।

इस मौके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना को पश्चिम बंगाल में लागू होने के मौके को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बन चुकी है। अब तक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक उपचार हो चुके हैं, जिनकी कुल लागत 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। इस योजना के तहत इलाज कैशलेस और पेपरलेस होगा और मरीज देशभर के 36,000 से अधिक एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों के जेब से होने वाले खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2018 से पहले 64.6 प्रतिशत था और अब घटकर 43.4 प्रतिशत के आसपास आ गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस योजना की पॉर्टिबिलिटी सुविधा के कारण पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में इलाज करा सकेंगे और उन्हें कैशलेस सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों में एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम जैसे प्रयासों से किशोरियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में इस दिशा में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है।

इंडी गठबंधन की बैठक पर भाजपा का तंज, कहा- कमजोर पड़ चुकी है जमीन, आने वाले समय में कार में होगी बैठक

नई दिल्ली। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ चुकी है। सोमवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सांसद डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि ये इनकी बैठक नहीं बल्कि इंडी गठबंधन वालों का एक ड्रामा चल रहा है। ये हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में इनकी बैठक होगी। राहुल गांधी ने चुनाव हारने का शतक लगाया है, लेकिन आज ऐसे हंस रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए हैं। संबित पात्रा ने कि यह गठबंधन हर दो महीने में बैठक करने की योजना बना रहा है। पहले इंडी गठबंधन की बैठकें बड़े स्तर पर, जैसे कि बेंगलुरु के स्टेडियम में होती थीं, जहां सभी नेता एकजुट होकर हाथ पकड़कर खड़े होते थे। अब ये बैठकें सिमटकर केवल एक कमरे तक रह गई हैं, जैसे कि कॉन्स्टिच्युशन क्लब ऑफ इंडिया में और अब इनमें पहले जैसा जनसमर्थन या भीड़ नहीं दिखती। तीसरी या चौथी बैठक तक मुझे लगता है कि ये बैठकें किसी कार के अंदर होने लगेंगी। संबित पात्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बैठक में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, जब उन्होंने ममता बनर्जी को देखा होगा, तो शायद यह सोच रहे होंगे कि कुछ ही समय में मेरी भी वही हालत होने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी राहुल गांधी मौजूद होते हैं, वहां किसी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं रहता। संबित पात्रा ने कहा कि

तमिलनाडु में कांग्रेस ने तुरंत जाकर एक अन्य दल के साथ गठबंधन किया। सरकार बनाई, जबकि पश्चिम बंगाल में हार के बाद विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और एसआईआर का रोना रो रहा है। एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, लेकिन सरकार बना ली, लेकिन जब बंगाल में हार गए तो एसआईआर को कोस रहे हैं, एसआईआर का रोना रो रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की जमीन पर पकड़ कमजोर हो गई है और जनता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इंडी गठबंधन की यह बैठक राजनीतिक पाखंड है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग करते हैं। लेकिन पिछली बार जब नारी सशक्तिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, सब नदारत थे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। जनता ने इन्हें पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया है।

शुभेंदु सरकार का एक महीना : अवैध घुसपैठियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए सख्त कदम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के पहले एक महीने ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों की शुरूआत के संकेत दिए हैं। ब्रिगेड परेड मैदान में पिछले महीने 09 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ कई फैसले लिए। पहले ही महीने में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लागू की और करीब 32 लाख महिलाओं के खाते में तीन-तीन हजार रुपये आए हैं। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर भी शुरू हुआ है जो नारी शक्ति के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा सरकार के शरूआती महीने में सबसे बड़ा फोकस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर रहा। विभिन्न स्तरों पर हुई जांच और कार्रवाई में कई राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें कई बड़े नाम

भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री सुजीत बोस, स्वरूप विश्वास, दिलीप मंडल, जहांगीर खान, असित मजूमदार, सब्यसाची दत्त और रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे नाम चर्चा में रहे हैं। इसी अवधि में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ी है। खासकर शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ की प्रक्रिया तेज हुई। सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही कई मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय भी लिया गया है। शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए भी नए कदम उठाए गए हैं।

अब राशन सिस्टम में AI की एंट्री, 2031 तक चलेगी स्मार्ट-पीडीएस योजना

नई दिल्ली। अब सरकारी राशन व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने 'स्मार्ट-पीडीएस' योजना को साल 2031 तक जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक और एआई सिस्टम से राशन बांटने में पारदर्शिता बढ़ेगी और फजीवांड़े पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों की पहचान डिजिटल तरीके से होगी। सरकार लाभार्थियों का रियल टाइम रिकॉर्ड तैयार करेगी, जिससे गलत

नाम हटाने और सही लोगों तक अनाज पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राशन से जुड़ी शिकायतें अब फोन कॉल, व्हाट्सऐप और चैटबॉट के जरिए भी दर्ज कराई जा सकेंगी। सरकार का दावा है कि इससे लोगों की परेशानियां जल्दी सुनी जाएंगी। राशन ढोने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखी जाएगी। अनाज की बोरियों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे ताकि माल कहां से चला और कहां पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी मिल सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 80 करोड़ लोग हर महीने राशन योजना का फायदा लेते हैं। माना जा रहा है कि नई तकनीक आने से राशन वितरण पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगा।

पत्रकार - लव कुमार

विद्युत विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से दो भैंसों की मौत

बगरैन (बदायूं) में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा कवर न होने और तार में करंट उतरने से दो भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत भैंसें सर्वेश कुमार पुत्र भगवान पाल निवासी बगरैन की बताई जा रही हैं।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के समय बगरैन जेई को कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद करा दी जाती, तो दोनों भैंसों की जान बच सकती थी। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था न होने और खुले तारों में करंट दौड़ने से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं बगरैन चौकी पुलिस स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति को शांत कराया।

संवाददाता — एके सोनी, बदायूं

कर्नपुरा की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

विद्यालय, तालाब और रास्ते की जमीन पर फजीवाड़े से कब्जा करने का दावा, जांच की मांग तेज गांडेय अंचल के कर्नपुरा में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सार्वजनिक उपयोग की जमीन को निजी संपत्ति बताकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर गांव में आक्रोश बढ़ गया है और ग्रामीण प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त को सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि

मौजा कर्नपुरा, थाना संख्या-575 के खाता संख्या-19 और प्लॉट संख्या-05 की करीब 6.40 एकड़ गैरमजरुआ सरकारी भूमि पर अवैध दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में रही है, जहां सरकारी विद्यालय संचालित होता है, जलाशय स्थित हैं तथा गांव के लोगों का प्रमुख आवागमन मार्ग भी इसी भूमि से होकर गुजरता है। फर्जी कागजात बनाकर रसीद कटवाने का आरोप शिकायतकर्ता कृष्णा राणा समेत कई ग्रामीणों का आरोप है कि कर्नपुरा निवासी जीतू राणा ने कुछ कथित भू-माफियाओं के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसी के आधार पर ऑनलाइन रसीद कटवा ली।

(संचित कुमार)

बालचंद सैनी इंटर कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न

हरिद्वार (ढढेरी ख्वाजगीपुर): चौधरी बालचंद सैनी इंटर कॉलेज में मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री श्री शोभाराम प्रजापति जी और राज्य मंत्री श्री श्यामवीर सैनी जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलियर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अरुण सैनी जी ने भी

विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों और परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मुख्य अतिथियों ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए विद्यालय के अध्यापक गणों की भी सराहना की, जिनकी कड़ी मेहनत से छात्र इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम का सुंदर और व्यवस्थित संचालन भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजीव सैनी जी द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के युवा शक्ति जिला महासचिव आर्यन सैनी ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने आयोजन समिति के रविंद्र सैनी जी, यशवीर सैनी जी, आशीष सैनी जी और उनकी संपूर्ण टीम को इस शानदार प्रयास के लिए बधाई व शुभकामनाएं दीं।

(रिपोर्टर निखिल सैनी, सहयोगी बालेश सैनी)

हमारे नए अचीवर

नीलम सैनी
जोनल एडवाइजर

सैयद कामरुल हसन
जोनल एडवाइजर

सुनील सिंह
जोनल एडवाइजर

अरुण कुमार मिश्रा
एरिया एडवाइजर

तबिश इमरान
एरिया एडवाइजर

बीना मिश्रा
एरिया एडवाइजर

अनीता भोज
एरिया एडवाइजर

नीलम गुप्ता
न्यूज सपोर्टर

आइशा
न्यूज सपोर्टर

अफसर अली
न्यूज सपोर्टर

रामेइस नमानी
न्यूज सपोर्टर

शंजाबीन काजी
न्यूज सपोर्टर

सुरेंद्र सिंह
न्यूज सपोर्टर

दिनेश कुमार चितकारा
न्यूज सपोर्टर

मुस्तफा हसन
न्यूज सपोर्टर

सुमित चौधरी
न्यूज सपोर्टर

मंजू बिष्ट
न्यूज सपोर्टर

मुजम्मिल अंसारी
न्यूज सपोर्टर

शादी के नाम पर ठगने वाले 'लुटेरी दुल्हन' गिरोह का पदार्फाश, छपार पुलिस ने दुल्हन समेत 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर: जनपद की छपार थाना पुलिस ने सीधे-साधे परिवारों को शादी के झांसे में लेकर जेवरात और नगदी ठगने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पदार्फाश किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह की मुख्य सरगना यानी 'लुटेरी दुल्हन' समेत तीन महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला आरोपियों की पहचान सोनाक्षी, उसकी मां कामिनी और सहयोगी आशा के रूप में हुई है, जो सभी दुर्गाविहार, नजीबाबाद (बिजनौर) की रहने वाली हैं। पुलिस ने इनके पास से ठगे गए सोने-चांदी के आभूषण जैसे मंगलसूत्र, झुमकी, अंगूठी, पायल और बिछुए भी बरामद कर लिए हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित पिता ने छपार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार, ग्राम घुमावटी निवासी रविन्द्र नाम के एक बिचौलिए ने उनके बेटे की शादी कराने का झांसा दिया और सोनाक्षी नाम की लड़की की फोटो दिखाकर शादी तय कर ली। इसके बाद हरिद्वार के एक मैरिज होम में दोनों की शादी करा दी गई, जहाँ दूल्हा पक्ष ने दुल्हन को सोने-चांदी के गहने चढ़ाए। लेकिन शादी के अगले ही दिन दुल्हन सोनाक्षी सारे आभूषण समेटकर रंगे हाथों फरार हो गई। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने कुबूल किया कि वे एक संगठित गिरोह चलाती हैं, जो ऐसे परिवारों को निशाना बनाता है जिनकी शादी होने में दिक्कत आ रही होती है। शादी के नाम पर मोटी रकम ऐंठने और किसी मंदिर या धर्मशाला में फेरे लेने के महज एक-दो दिन बाद ही सोनाक्षी मौका पाकर जेवरात लेकर रफूचक्कर हो जाती थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और गिरोह के फरार साथी रविन्द्र की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

रिपोर्टर: निखिल सैनी

तेज आंधी-तूफान व बारिश से हुई मौतों पर पीड़ित परिवारों को मिली सहायता राशि

बदायूं। जनपद में हाल ही में आई तेज आंधी, तूफान एवं बारिश के दौरान हुई दुःखद घटनाओं में दो महिलाओं की असामयिक मृत्यु हो गई थी ग्राम तर्क परौली, परगना इस्लामनगर, तहसील बिसौली निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री अमर सिंह की पेड़ गिरने से दबकर मृत्यु हो गई थी। वहीं ग्राम फतेहपुर बीरमपुर, तहसील बिसौली निवासी श्रीमती रामश्री पत्नी श्री छत्रपाल की टीन शेड गिरने से मौत हो गई थी। शासन द्वारा अनुमन्य सहायता राशि पीड़ित परिवारों को प्रदान की गई। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं जिलाधिकारी बदायूं की उपस्थिति में परिजनों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। मंत्री एवं जिलाधिकारी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया

ए.के .सोनी
दिल्ली क्राइम प्रेस, बदायूं

मेरठ मिशन शक्ति फेज-5.0' के तहत लिसाड़ी गेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 720 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

मेरठ: जनपद में अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के आदेशानुसार और एसपी सिटी के निर्देशन में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, 'मिशन शक्ति फेज-5.0' (द्वितीय चरण) के तहत थाना लिसाड़ी गेट की मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी और पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा नशा तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 15 मई 2026 को खुशहाल नगर पानी की टंकी के पास मैदान से अभियुक्त हासिम उर्फ सोनू (पुत्र मेहरबान) को रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद कॉलोनी, समर गार्डन (लिसाड़ी गेट, मेरठ) का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 26 वर्ष है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 720 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। माल बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सराहनीय कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना प्रभारी दलवीर सिंह, मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी महिला उपनिरीक्षक सुमित प्रियंका शर्मा, उपनिरीक्षक सुमित नायक, महिला कांस्टेबल सोनम, मोनी और कांस्टेबल कृष्ण वीर व काव्य वशिष्ठ शामिल रहे।

रिपोर्टर: निखिल सैनी,
सहयोगी शाहिद हसन

27.5 करोड़ खर्च, फिर भी प्यासा बेरदोंगा: AIFB का आरोप - नेता-अधिकारी मौज में, जनता को पानी नहीं

गिरिडीह: सदर प्रखंड के बेरदोंगा गाँव में जल संकट गहराता जा रहा है। आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) ने आरोप लगाया है कि 27.5 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना के बावजूद ग्रामीण पिछले एक महीने से बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार 1 मई, फिर 14 मई और 24 मई को लगातार धरना-प्रदर्शन और सत्याग्रह के बावजूद जिला प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। AIFB नेताओं ने कहा कि "करोड़ों की योजना सिर्फ कागजों पर है। धरातल पर जनता प्यास से बेहाल है, जबकि विधायक-सांसद-नेता-अधिकारी मौज में हैं।" आगे की रणनीतिः पानी की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों और AIFB ने 30 मई 2026 को उपायुक्त, गिरिडीह के समक्ष जोरदार आंदोलन करने का निर्णय लिया है।

रिपोर्ट संचित कुमार

हमारे सहयोगी संरक्षक एवम् ब्यूरो प्रमुख

प्रधान सम्पादक – नरेन्द्र कुमार

सहयोगी संरक्षक
अनिल सेठी

सह कार्यकारी - संपादक दिनेश शर्मा

हमारे स्वतंत्र व सत्यापित रिपोर्टर

राजकुमार कश्यप	(दिल्ली)
मुकेश गुप्ता	(दिल्ली)
अशोक कुमार	(गुरुग्राम)
सुशील कुमार	(करनाल)
राम नरेश	(कुशीनगर)
मो.शरीफ	(दिल्ली)
अभिषेक कुमार	(दिल्ली)
राज हुसैन	(कुशीनगर)
ध्रुव सेठी	(पंजाब)
विक्रमादित्य सिंह	(सीधी)
सावित्री सिंह	(सीधी)
निखिल सैनी	(मुजफ्फरनगर)
सत्येंद्र सैनी	(मुजफ्फरनगर)
रविकरन सिंह अलीगढ	(उ. प्र)

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री, लेख, रचनाओं, एवम् विज्ञापनों में लेखकों और विज्ञापन दाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए दिल्ली क्राईम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा की किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही मान्य होगा।

विशेष :- किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार केवल संपादक को है।

61/9 अशोक नगर दिल्ली - 110018
Customer Care No.
8744884766

ADVERTISMENT RATE TARIFF PLAN

FULL PAGE | HALF PAGE | QUARTER PAGE

FULL FRONT PAGE	₹ 1,20,000/-
FULL INNER PAGE	₹ 60,000/-
FULL BACK PAGE	₹ 90,000/-
HALF FRONT PAGE	₹ 66,000/-
HALF PAGE INNER	₹ 36,000/-
HALF PAGE BACK	₹ 51,000/-
QTR. PAGE FRONT	₹ 36,000/-
QTR. PAGE INNER	₹ 21,000/-
QTR. PAGE BACK	₹ 30,000/-

Classifieds Ads. Per Column / 3 CM. Rs.2100/-
Visiting Card Size Advertisements:
Front Page Rs. 6000/- Back Page Rs. 4500/-
Inner Page Rs.3000/-

dc pess JUNE 2026:Layout 1 09-06-2026 18:04 Page 8

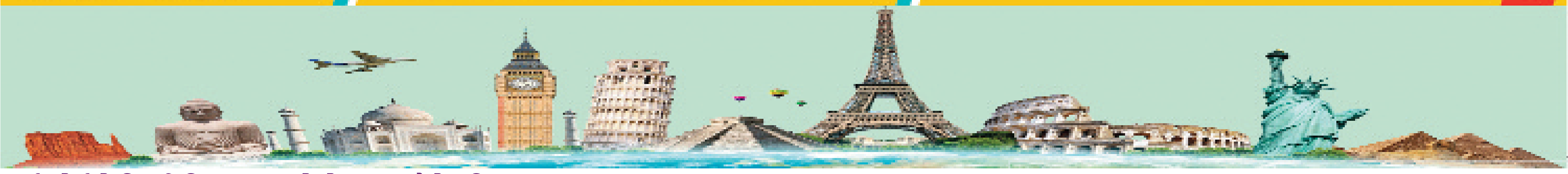

हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना, पोलो ग्राउंड जैसे हरित क्षेत्र को अधिग्रहित करने के फैसले पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के दिल्ली जिमखाना, पोलो ग्राउंड जैसे हरित क्षेत्र को अधिग्रहित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिल्ली में काफी कम हरित क्षेत्र है। उसे हटाने के बाद प्रदूषण से दम घु-टकर हमारी मौत हो जाएगी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वे-केशन बेंच ने ये टिप्पणी इंडियन पोलो एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र स-रकार से पूछा कि आपको पोलो ग्राउंड क्यों चाहिए। आपको दिल्ली जिमखाना समेत सभी हेरि-टेज ढांचों का क्या करेंगे। आप उनका क्या करने वाले हैं। आप वहां बीस मंजिला बिल्डिंग खड़ी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके में थोड़ी बहुत सांसे बची हुई हैं। हम सभी घुटकर मरने वाले हैं। सरकार को 200 सालों में इनकी कोई जरुरत नहीं हुई। दिल्ली में एक छोटा सा फेफड़ा है, आप उसे भी चाहते हैं कि ले लें। दरअसल, इंडियन पोलो एसोसिएशन ने याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। पोलो एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार के खाली करने के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने नोटिस पर रोक संबंधी अर्जी पर कोई विचार नहीं किया और एक सामान्य नोटिस जारी कर दिया।

इसपर उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट को निर्देश दिया कि वो खाली करने के नोटिस पर रोक की अर्जी पर फैसला करें। सुनवाई के दौरान केंद्र स-रकार के वकील आशीष दीक्षित ने केंद्र सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केवल रक्षा जरुरतों के लिए इन इलाकों का सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या ऊंची बिल्डिंग बनना जनता के हित में है। दिल्ली में केवल ऊंची बिल्डिंग है। इसे भगवान ही बचा सकते हैं।

दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD का सख्त एक्शन, छुट्टी के दिन रविवार को भी गरजा बुलडोजर

नई दिल्ली। सैदुलाजाब और हौजरानी की घटना के बाद राजधानी दिल्ली में रविवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके बाद दिल्ली में जगह-जगह अवैध निर्माण गिराए गए। इसमें संम्रात अवैध कालोनी सैनिक फार्म में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पर निर्माण पर बिल्कुल पाबंदी है। इसलिए हाल में हुए निर्माण पर एमसीडी अब कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही एमसीडी ने कृष्णा पार्क इलाके में कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि निगम की कार्रवाई आम तौर पर सोमवार से शनिवार को होती है लेकिन रविवार को छुट्टी होने के बाद भी पहली बार कार्रवाई देखी गई है।

सभी को सख्त निर्देश – निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन-जिन अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले जो कानूनी प्रक्रिया होती है वह पूरी होती जा रही है उसे गिराया जा रहा है। सभी को सख्त निर्देश हैं कि किसी भी अवैध निर्माण पर कोताही न बरतें। अधिकारी ने बताया कि सोमवार को भी विभिन्न जोन में एक्शन तय हैं। सीलिंग और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर भी निरीक्षण भी चल रहा है वहीं निगम की टीम भी अपने-अपने स्तर पर निरीक्षण कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली स-रकार के अधिकारियों के साथ मिलकर अब तक 130 स्थानों पर निरीक्षण हो चुके हैं। इसमें उत्तरी जिले द्वारा 16 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस दिए गए हैं। इसी प्रकार नई दिल्ली जिले में चार निरीक्षण किए गए हैं इसमें नियमों का उल्लंघन पाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दक्षिण पश्चिम जिले में 10, दक्षिणी-उत्तरी जिले में छह, पूर्वी में 15, उत्तर-पश्चिम जिले में 13, उत्तर-पूर्वी जिले में पांच, मध्य उत्तरी जिले में 19, मध्य जिले में 11 निरीक्षण किए गए हैं। इसमें सीलिंग और कारण बताओ के नोटिस हैं। अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण और लाइसेंस की शर्तों के विपरित चलने वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली इकाइयों पर प्रमुख तौर पर कार्रवाई हो रही है। अब तक निगम 97 संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। जबकि 137 पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है।

सोनिया विहार 'ओ जोन' क्षेत्र में सरकार 138 करोड़ रुपए की लागत से डालेगी सीवर लाइन, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में 'ओ जोन' क्षेत्र को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। रविवार शाम को सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी व मंत्री कपिल मिक्षा और प्रवेश वर्मा के साथ 138 करोड़ रुपये की लागत से 44 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डालने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोनिया विहार, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी और सभापुर एक्सटेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। सिंचाई विभाग ने कुछ ही दिनों पहले सोनिया विहार समेत कई क्षेत्रों में ओ जोन के चेतावनी बोर्ड लगाए थे। इसमें कहा गया था यह क्षेत्र यमुना खादर में आते हैं। यहां निर्माण कार्य की अनुमति नहीं। इसके बाद से यहां के लोग सहमे हुए थे कि उनके मकान टूटेंगे या रहेंगे। सरकार ने सीवर परियोजना के जरिये ओ जोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को साधने की कोशिश की।

विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोग लंबे समय से जल निकासी, सीवर व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स-रकार प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, धरातल पर परिणाम देना है। सोनिया विहार, मिलन गार्डन, चौहान पट्टी और सभापुर एक्सटेंशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। पुरानी जलापूर्ति लाइनों को बदलने, पुराने सीवरों की मशीनों से सफाई कराने तथा पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा एक नए अस्पताल की मांग भी उनके संज्ञान में आई है और दिल्ली सरकार भविष्य में इस दिशा में भी सकारात्मक पहल करेगी।

सुंदरीकरण की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य करेगी

सिग्नेचर ब्रिज से पुश्ता मार्ग तक सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य करेगी। सोनिया विहार यमुना तट के किनारे एक आधुनिक और आकर्षक रिवर फ्रंट विकसित करने की संभावनाओं पर भी सरकार विचार कर रही है। उनका मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई दिशा दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विगत 12 साल में से 11 साल भाजपा विपक्ष में थी फिर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार दिल्ली विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया। नई सड़के बनाई। मंत्री कपिल मिश्रा ने दावा किया ओ-जोन का बोर्ड अब कूड़े में फेंकने लायक हो गए हैं। क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्र-कार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां किसी भी घर की एक ईंट को कोई हाथ नहीं लगा सकता।

क्षेत्र में सीवर व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या

कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सोनिया विहार और सभापुर के निवासी निश्चिंत रहें। यहां किसी के घर को कोई नुकसान नहीं होगा और न ही किसी की एक ईंट हिलेगी। पूर्व की सरकारों ने क्षेत्र के लोगों को विकास कार्यों से वंचित रखा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कार्य की शुरूआत होने जा रही है। इस क्षेत्र में सीवर व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या थी। यहां के लोगों को कभी-कभी यह चिंता भी रहती थी कि उनकी कालोनी का भविष्य क्या होगा। लेकिन अब जनहित में काम करने की नीयत रखने वाली सरकार इस क्षेत्र का विकास करेगी और इसे बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। बता दें ओ जोन क्षेत्र डीडीए ने बनाएं हैं। यह वह जोन होते हैं, जो यमुना खादर में आते हैं। यहां किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है।

टीएमसी में संकट गहराया, काकोली घोष सहित 20 सांसदों का राजग को समर्थन देने का फैसला

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को दावा किया कि कम से कम 20 सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का समर्थन करने का फैसला किया है। इस संबंध में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। पश्चिम बंगाल के बारासात लोकसभा क्षेत्र की सांसद काकोली घोष ने बताया कि 20 सांसदों की ओर से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें केंद्र की सत्तारूढ़ राजग सरकार का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की गई है। घोष ने कहा कि वे लोकसभा में टीएमसी की मुख्य सचेतक हैं और यह निर्णय अन्य सांसदों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य सचेतक पद से हटाने का फैसला मनमाना और एकतरफा था। पार्टी अध्यक्ष ने भले ही मेरे स्थान पर किसी और की नियुक्ति की घोषणा कर दी हो, लेकिन इससे संवैधानिक और संसदीय स्थिति रातोंरात नहीं बदल जाती। हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है। हमारा मानना है कि भविष्य में हमारी राजनीतिक दिशा राजग के साथ होनी चाहिए। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों में टीएमसी के कुल 40 सांसद हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सदस्य हैं।

DELHI CRIME PRESS की सदस्यता के लाभ

इच्छुक व्यक्ति समाचार पत्र की आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
सदस्यता लेने के बाद मिलने वाले फायदे।
प्रभावशाली गौरवशाली राष्ट्रीय सेवा को समर्पित रोजगार।
निशुल्क विज्ञापन (एक विजिटिंग कार्ड साइज)।
सदस्यता पहचान पत्र व पेन।
दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के स्टीकर (कार व बाइक के लिए)।
अपने क्षेत्र में अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या पर लेख समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का सुअवसर।
दिल्ली जर्नलिज्म एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट (पत्रकारिता प्रशिक्षण संस्थान) से प्रशिक्षण प्राप्त कर पत्रकार बनने का सुअवसर

स्वामी, प्रकाशक एवम मुद्रक इंद्रा द्वारा रॉयल ऑफसेट, 489 एफ.आई.ई, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली - 110092 से मुद्रित कराकर एम 64, हरी नगर, नई दिल्ली -110064 से प्रकाशित किया गया। संपादक : इंद्रा
Customer Care No. 8744884766, For News & Advertisement 8744882188, Email- info@delhicrimepress.in, website - delhicrimepress.in